

कुमाँऊ मंडल में श्वेत क्रान्ति की सम्भावनाएँ एवं समस्याएँ (जनपद नैनीताल के विशेष संदर्भ में)

*डा० हेमा मेहरा

**डा० पदम एसबिष्ट

***डा० अशोक कुमार

कुमाँऊ मण्डल की भौगोलिक बनावट मुख्यतः पर्वतीय है, यहाँ पर आवागमन एवं यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध न हो पाने के कारण यहाँ के निवासियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। विषय भौगोलिक परिस्थितियों व आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कई दशकों से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास, जनपद के तराई व मैदानी क्षेत्र की तुलना में कम ही हुआ है। फलस्वरूप यहाँ से परिवारों को रोजगार के लिए अन्य स्थानों में पलायन करना पड़ता है। विगत दो दशकों में श्वेत क्रान्ति के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप डेरी उद्योग ने देश की राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शोध के उद्देश्य :-

1. पर्वतीय क्षेत्र में श्वेत क्रान्ति की सम्भावनाओं का पता लगाना।
2. श्वेत क्रान्ति की राह में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना।
3. श्वेत क्रान्ति से ग्रामीण अंचल की जनता की आय का पता लगाना।

परिकल्पनायें

1. श्वेत क्रान्ति के फलस्वरूप ग्रामीण अंचल के परिवारों की आय में वृद्धि हो रही है।
2. श्वेत क्रान्ति से ग्रामीण अंचल में रोजगार के स्तर में वृद्धि हो रही है।

शोध विधि :- शोध कार्य के लिए शोधार्थी द्वारा त्रिस्तरीय निर्देशन प्रणाली का प्रयोग किया गया। प्रथम स्तर पर जनपद के उस विकास खण्ड का चयन किया गया जहाँ पर दुग्ध उत्पादन अधिक होता है। द्वितीय स्तर पर चयनित विकासखण्ड से पाँच-पाँच गाँवों का लाटरी विधि द्वारा चयन किया गया तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित ग्राम से दस-दस दुग्ध उत्पादक परिवारों को लौटरी विधि द्वारा चुना गया इस प्रकार कुल पचास दुग्ध उत्पादक किसानों के परिवारों का अध्ययन किया गया है। उक्त पचास दुग्ध उत्पादक परिवार से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया गया है तथा विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष निकाले गये तत्पश्चात सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। विकास खण्ड भीमताल का चयन अध्ययन क्षेत्र के लिए किया गया क्योंकि यहाँ पर दुग्ध उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है।

2

कुमाँऊ के पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध विकास का इतिहास बहुत पुराना है। देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात सन् 1951 से पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् 1951-55-56 दुग्ध डेरी विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया। दुग्ध व्यवसाय ही पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक मात्र ऐसा व्यवसाय है, जो खेती के साथ-साथ नियमित आय उपलब्ध कराने, बेरोजगारी दूर करने ग्रामीण कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

*एसिस्टेंट प्रोफेसर रा० महा० वि० गंगोलीहाट पिथौरागढ़,

**प्रोफेसर डी० एस० बी० परिसर कुमाँऊ विश्वविद्यालय नैनीताल

***एसिस्टेंट प्रोफेसर डी० एस० बी० परिसर पर्यटन विभाग नैनीताल

नैनीताल जनपद में पशुपालन कृषि के पश्चात आय का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। दुधारु पशुओं की उन्नत नस्ल के कारण "लालकुआँ दुग्ध डेरी" जनपद के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी दुग्ध आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनके विभिन्न दुग्ध उत्पाद ऑचल के नाम से व्यख्यात हो रहे हैं।

श्वेत क्रान्ति की अनेक क्षेत्रों में कामयाबी और पशुपालन की परम्परा को देखते हुए राज्य गठन के बाद सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में डेरी विकास की संभावनाओं को साकार करने के प्रभावी कदम उठाये हैं। कुमाऊँ में पशुपालन एवं डेरी विकास की अपार संभावनाये है पशुपालन विकास की अपार संभावनाओं को साकार रूप देने के लिए उत्तम नस्ल के पशुओं, अच्छा चारा, स्वास्थ्य की वेहतर सुविधायें, उत्पादों की गुणवत्ता एवं बाजार की उपलब्धता मुख्य मानक है।

पशुपालन को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि परम्परागत विधियों के साथ-साथ नवीनतम तकनीकी विधियाँ अपनायी जाये एवं पशुओं के नस्ल में सुधार के साथ उनकी स्वास्थ्य रक्षा एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करने की समुचित व्यवस्था की जाये

जनपद नैनीताल भीमताल ब्लॉक सड़कों से जुड़ा होने के साथ ही विकासखण्ड का लगभग 27 प्रतिशत परिवार दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए है। जिस कारण इसे शोध कार्य के लिए चुना गया, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध कार्य करने वाले परिवार अपने दुध को एकत्र कर बिक्रय हेतु समितियों (डेरी) तक पहुचाने को कार्य करते है। प्रतिदिन समितियों (डेरी) से भुगतान प्राप्त न होने के कारण 07 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपना दुग्ध समितियों (डेरी) को न देकर सीधे बाजार एवं घरों में बिक्रय कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को पाले जाने का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं दुग्ध प्राप्ति से रहा है।

3

तालिका संख्या 01

न्यादर्श क्षेत्र में सर्वेक्षित दुग्ध उत्पादक परिवारों का कुल दुग्ध उत्पादन, घर पर खपत एवं बिक्री दुग्ध का विवरण

क्रमिक	सर्वेक्षित न्यायदर्श दुग्ध उत्पादक ग्राम का नाम	सर्वेक्षित उत्पादक परिवारों की सं०	सर्वेक्षित परिवारों में जानवरों की सं०			सर्वेक्षित परिवारों में कुल दुग्ध उत्पादन (ली०) में	सर्वेक्षित परिवारों की घर पर खपत (ली०) में	सर्वेक्षित परिवारों द्वारा बिक्रय किया गया दुग्ध की मात्रा (ली०) में	औसत उत्पाद प्रतिपरिवार (ली०) में	औसत उपभोग प्रतिपरिवार (ली०) में	औसत बिक्रय प्रतिपरिवार (ली०) में
			भैस	गाय	कुल						
1	पिनरौ	10	12 (18-18)	8 (15.68)	20 (17.09)	73 (19.57)	21 (20.92)	52 (19.33)	7.3 (19.57)	2.1 (20.19)	5.2
2	भौर्सा	10	18 (27.27)	11 (21.56)	29 (24.78)	105 (28.15)	26 (25)	79 (29.36)	10.5 (28.15)	2.6 (25)	7.9
3	अम्मियाँ	10	09 (13.63)	15 (29.41)	24 (20.51)	65 (17.42)	18 (17.30)	47 (17.47)	6.5 (17.42)	1.8 (17.30)	4.7
4	बडैत	10	13 (19.69)	09 (17.64)	22 (18.80)	71 (19.03)	19 (18.26)	52 (19.33)	7.1 (19.03)	1.9 (18.26)	5.1
5	स्पूडा	10	14 (21.21)	08 (15.68)	22 (18.80)	59 (15.81)	20 (19.23)	39 (14.49)	5.9 (15.81)	2.0 (19.23)	3.9
Total	5	50	66 (100)	51 (100)	117 (100)	373 (100)	104 (100)	269 (100)	37.3 (100)	10.4 (100)	26.9

कोष्ठक में प्रतिशत को दर्शाया गया है।

(स्रोत प्राथमिक सर्वे पर आधारित)

4

तालिका 01 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित ग्रामों में कुल 373 ली० मासिक दुग्ध का उत्पादन किया गया जिसमें से 15.81 प्रतिशत स्यूडा ग्राम में, 19.03 प्रतिशत बडैत ग्राम में, 17.42 प्रतिशत अम्मियाँ ग्राम, 28.15 प्रतिशत भौर्सा ग्राम तथा 19.57 प्रतिशत पिनौर ग्राम में दुग्ध उत्पादन किया गया। भौर्सा ग्राम में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हरी घास प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। मासिक दूध की खपत 104 ली० रही जिसमें से क्रमशः पिनौर में 20.92 भौर्सा 25 अम्मियाँ 17.30 बडैत 18.26 तथा स्यूडा में 19.23 प्रतिशत दूध की खपत की गयी। भौर्सा व पिनौर गाँवों में दुग्ध की घरेलू खपत अन्य सर्वेक्षित गाँवों की तुलना में सबसे अधिक रही क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अन्य गाँवों की तुलना में अधिक है। तालिका 01 से यह भी स्पष्ट है कि सर्वेक्षित गाँवों में कुल 269 ली० की मासिक बिक्री की गयी जिसमें से क्रमशः पिनौर में 19.33 भौर्सा 29.36 अम्मियाँ 17.47 बडैत 19.33 तथा स्यूडा में 14.49 प्रतिशत दुग्ध की बिक्री की गयी। भौर्सा व पिनौर ग्रामों में दुग्ध की अधिक मात्रा होने से बिक्री भी अधिक की जाती है।

सर्वेक्षित क्षेत्र में मासिक औसत उत्पादन 37.3 ली०, मासिक उपभोग 10.4 ली० तथा मासिक औसत बिक्री 26.9 ली० रही।

कुल वार्षिक दुग्ध उत्पादन ली० में	373×12=4476
कुल वार्षिक दुग्ध खपत ली० में	104×12=1248
कुल वार्षिक दुग्ध बिक्रय ली० में	269×12=3228
कुल वार्षिक औसत दुग्ध उत्पादन ली० में	37.3×12=447.6
कुल वार्षिक औसत दुग्ध उपभोग ली० में	10.4×12=128.8
कुल वार्षिक औसत दुग्ध बिक्रय ली० में	26×9×12=322.8
औसत दुग्ध व्यवसाय की वार्षिक बिक्री से आय	322.8×33=10652.4
औसत दुग्ध व्यवसाय की वार्षिक बिक्री पर प्रोत्साहन से आय	322.8×4=1291.2
कुल औसत दुग्ध व्यवसाय की वार्षिक बिक्री से आय	10652+41291.2=11943.6

राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन की ओर जनता का रुझान बढ़ने लगा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा है सर्वे के दौरान दुग्ध उत्पादक सर्वेक्षित परिवारों ने यह बतलाया कि दुग्ध उत्पादन से उनकी आय में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यदि सरकार दुग्ध उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करे तो ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगार नवयुवकों का पलायन काफी हद तक रूक सकता है।

दुग्ध संघ/दुग्ध समितियाँ के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का भुगतान 33 रुपये प्रति लीटर की दर से किया जाता है।

वर्तमान में महंगाई व दुग्ध उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादक की प्रगति के लिए नवम्बर सन् 2014 से दुग्ध संघ के दुग्ध मूल्य क्य दर के अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को रुपये 04 प्रति ली० की दर से अलग से प्रोत्साहन मूल्य दिया जा रहा है।

निष्कर्ष—

उपर्युक्त अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में पशुपालन के विकास की असीम संभावनायें विद्यमान हैं। पशुधन ही ग्रामीण किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त व्यवसाय है। पशुधन आर्थिक वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। साथ ही दुग्ध व्यवसाय पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान, मजदूर व बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बुनियादी जरूरत है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस व्यवसाय की अपनी विशिष्टतायें हैं। इसका आधुनिकीकरण एवं विकास अति आवश्यक है।

सर्वेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि इस क्षेत्र के पशुपालक अत्यधिक परिश्रम के बावजूद भी इस व्यवसाय से अधिक लाभ अर्जित कर पाने में असमर्थ हैं। क्योंकि उत्तम किस्म के पशुओं का अभाव तथा परम्परागत पशुओं की प्रजाति के पालन के कारण लाभ की संभावनायें काफी कम हो जाती हैं। तकनीकी ज्ञान के अभाव में भी कुशलता पूर्वक ग्रामवासी इस व्यवसाय का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। यदि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय को अपनाने के लिए उन्हें तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के साथ सस्ते ब्याज पर ऋण व अच्छी किस्म के पशुओं की व्यवस्था की जाये साथ ही सरकार को दुग्ध की कीमत में उचित सुधार किया जाये तथा दुग्ध की बिक्री की गारंटी के साथ-साथ पशुओं को बीमा कराये जाये।

सुझाव—

1. दुग्ध समितियाँ द्वारा उत्पादकों को अच्छे नस्ल के पशुओं की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
2. दुग्ध समितियाँ द्वारा उत्पादकों को अच्छे नस्ल के पशुओं को सुलभ एवं सस्ते दामों में प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
3. दुग्ध समितियों द्वारा उत्पादकों को पशुओं के लिए पौष्टिक आहार में प्रयोग आने वाले चारे की जानकारी एवं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।
4. दुग्ध समितियों द्वारा उत्पादकों के पशुओं का उचित बीमा कराया जाना चाहिए।
5. रोजगार के साधन सीमित होने के कारण उत्पादक जो प्रति दिन की आजीविका चलाने के लिए बाजार एवं घरों में कम दामों में अपने दुग्ध को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे उत्पादकों को उनके दुग्ध की कीमत भुगतान प्रतिदिन करने की व्यवस्था दुग्ध समितियों द्वारा की जानी चाहिए।

संदर्भ—

1. पशुधन विकास में एक प्रयास, पशुपालन विभाग उत्तरांचल
2. आर्चैल, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, दिनांक 30.12.2015
3. स्मारिका, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० लालकुआँ नैनीताल 2001.02
4. डेरी विकास विभाग उत्तरांचल हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त परिचय।
5. डा० मिश्र रामचन्द्र 2001 उत्तरांचल में पशुपालन डेरी विकास।
6. स्मारिका, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० लालकुआँ नैनीताल 2003-04।
7. पशुपालन डेरी विभाग वार्षिक रिपोर्ट कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
8. श्वेत क्रान्ति योजना, दुग्धशाला विकास विभाग।
9. दुग्धशाला विकास विभाग 5 जुलाई 2015।
10. पाण्डे सीताराम निदेशक महिला डेरी विकास उत्तराखण्ड द्वारा जारी सूचना पत्रक।